

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2

देहरादून:

दिनांक: 13 जून, 2017

विषय:-

उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जनपदों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्रों में 100 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापन कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 942/टी0ए0सी/2017-18 दिनांक 12 मई, 2017 एवं पत्र संख्या: 884/वि0अनु0/02/शासन अनुदान/2017-18 दिनांक 08 मई, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है संलग्न सूचीनुसार राज्य के विभिन्न जनपदों (गढ़वाल मण्डल में-52नग व कुमायूं मण्डल में 48नग) में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्रों में 100नग हैण्डपम्प अधिष्ठापन कार्य हेतु धनराशि रु0 233.00लाख(रु0 दो करोड़ तैतीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान के अन्तर्गत प्राविधानित रु0 100.00लाख(रु0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।
- (ii) हैण्डपम्प का अधिष्ठापन से पूर्व जिलाधिकारी की संस्तुति आवश्यक रूप से प्राप्त की जाय।
- (iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।
- (iv) कार्य कराने से पूर्व मदवार दरें विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- (v) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आयोजन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- (vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।
- (vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार) ने स्थल का भली भौति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् देये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 वित्त नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा असंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

हैण्डपम्प लगाते समय यदि हैण्डपम्प में पानी नहीं निकलता है(ड्राई बोर) तो ध्यान पर नये प्रस्तावित स्थान का अनुमोदन भी जिलाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा।

सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-11/2017-18 लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-11-102-11 से स्थान्तरित)-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मांग डाला जायेगा।

नराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या- H 1706130739 2 जून, 2017 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश 12/XXVII(1)/2017, दिनांक 31-मार्च, 2017 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का सुनिश्चित किया जाय।

ह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या: 161 /XXVII(2)/2017 दिनांक 12-जून-2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

-हैण्डपम्पों के अधिष्ठान की जनपदवार सूची।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

33 (1)/उन्तीस(2)/17-2(14 पे0)/2017, तददिनांक।

-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

जाधिकारी, देहरादून।

स्थ निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

पट्ट कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।

ट निदेशालय, देहरादून।

अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।

फाईल।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

प्रेषक,

सेवा में,

पेयजल एवं स
विषय :- वित्तीय
महोदय,

2017 के रांदा
अन्तर्गत विभि
कुल रु0 1471
अवशेष धनराशि
धनराशि राज्य
स्थ जाने की

(i)

(ii)

जिलाधिकारी दे

(iii)

जायेगा। धनराशि
में नहीं किया जा

(iv)

अनुमोदन प्राप्त

(v)

अन्तर्गत शासकी

प्राप्त कर ली जा

ही धनराशि व्यय

vi)

नियंत्रक/मुख्य/

तो संबंधित वित्त

(vii)

भौतिक प्रगति का

कर दिया जाय।

के समय प्रतिपूर्ति